राजस्थान पत्रिका, पेज नंबर :- ०३
दिनांक :- २६/०५/२०२६

पेट्रोल-डीजल बचत और सादगी पर गुजरात सरकार ने उठाए कदम

सरकारी दौरों पर लगेगी लगाम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा

रात 11 बजे तक चलेगी मेट्रो ट्रेन

ई-व्हीकल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

गांधीनगर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और मितव्ययिता की अपील के बाद गुजरात सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि अब सरकारी विभागों में केवल अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा की जाएगी। अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और ई-मेल जैसे डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्षेत्रीय अधिकारियों को भी जहां संभव हो, वर्चुअल माध्यम से बैठकों में शामिल होने को कहा गया है। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों और केंद्र सरकार की बैठकों में भी ऑनलाइन भागीदारी को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़ विदेश यात्राओं, अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भागीदारी को हतोत्साहित किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का निर्णय: सरकार ने निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को मेट्रो, एसटी बस और रेलवे सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवा का समय रात 11 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्टेशन से गुरुकुल तक साइकिल चलाई।

राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में चलाई साइकिल

गांधीनगर. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक साइकिल चलाकर ईंधन बचत का संदेश दिया। वे अहमदाबाद से शताब्दी एक्सप्रेस से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक रेलवे रोड, आर्य समाज मार्केट, पैनोरमा चौक, बिरला मंदिर होते हुए साइकिल यात्रा की। इस यात्रा में उनके साथ भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खिलाड़ी और लगभग 200 साइकिलिस्ट शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईंधन की खपत कम करने की अपील की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्य में हवाई यात्रा और हेलिकॉप्टर का उपयोग पूर्णतः बंद कर दिया है। साथ ही अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या भी घटाई है।

निष्क्रिय किए जाएंगे अतिरिक्त सरकारी वाहन

सरकारी खर्चों में कटौती के तहत सभी विभागों में सरकारी वाहनों की समीक्षा होगी और अतिरिक्त वाहनों को निष्क्रिय किया जाएगा। एक से अधिक जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों को केवल एक मुख्य वाहन रखने और बाकी वाहन 'गवर्नमेंट व्हीकल पूल' में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अधिकारियों के पास ईवी या हाइब्रिड वाहन उपलब्ध हैं, उन्हें उन्हीं का उपयोग करने को कहा गया है।

अफवाह से बचें

प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट से बचें और संसाधनों का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उठाए गए इन कदमों से पेट्रोल-डीजल और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सरकारी तिजोरी पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।

सरकारी संस्थानों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा: इसके अलावा सभी सरकारी संस्थानों में स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीद नीति को मजबूत किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा तथा लोकार्पण कार्यक्रमों में वर्चुअल मॉडल अपनाने पर जोर रहेगा।

छह महीनों में सभी सरकारी कैंटीनों में पीएनजी अनिवार्य: अगले छह महीनों में सभी सरकारी कैंटीनों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्टिविटी अनिवार्य की जाएगी। सरकार ने अनावश्यक वस्तु संग्रह और घबराहट में खरीदारी रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने की भी घोषणा की है।

पेट्रोल-डीजल स्टॉक की रोजाना निगरानी के निर्देश

गांधीनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को गांधीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों, बजट घोषणाओं, शिक्षा और पेट्रोल-डीजल आपूर्ति सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि बैठक में राज्य में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से रोजाना पेट्रोल-डीजल स्टॉक की मॉनिटरिंग की जाए और जरूरत के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वाघाणी के मुताबिक राज्य सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं और प्रावधानों को तेजी से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। बजट की 80 प्रतिशत से अधिक नई घोषणाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। जबकि चुनाव आचार संहिता के कारण लंबित लगभग 20 प्रतिशत प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी देकर अमल में लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। प्रवक्ता मंत्री के मुताबिक 10 और 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता पर मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।